LOK SABHA

Thursday, December 12, 1968/Agrahayana 21, 1890 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

(MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

+

*691. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़ी हुई जातियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त पुस्तकें तथा छात्रवृत्तियां दी जाती हैं; और

(ख) किन राज्यों में उक्त प्रबन्ध नहीं किये गये हैं ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI MUTHYAL RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) Such arrangements have been made in all the States.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर-प्रदेश में कितने विद्यार्थी यह सुविधा पा रहे हैं ? क्या सरकार के पास इस के आंकड़े हैं ?

श्री मुत्थाल राव : यह आंकड़े मंगा-कर दे दिये जायेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मन्त्री महोदय को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि यह सुविधाएं यद्यपि कागज पर दी गई हैं किन्तु व्यवहार में उन के ऊपर आचरण नहीं हो रहा है तो क्या सरकार इस तरह की शिकायतों के बारे में जांच कराने के वास्ते तैयार है ?

श्री मुत्थाल राव : जब भी कभी इस तरह की शिकायतें हमारे पास आती हैं हम उन की छानबीन करवाते हैं और जैसे ही कोई पकड़ा जाता है उस को हम सबक देते हैं । साबित होने पर हम सजा भी देते हैं । कहने का मतलब यह है कि जब पैसा देते हैं और पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है तब जो उन के ऊपर हमें डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है वह एक्शन हम लेते हैं और कहते हैं कि सही तरीके से उन को पैसा दिया जाय ।

SHRI BISHWANATH ROY : May I know whether it is a fact that some of the facilities provided to the scheduled castes and scheduled tribes students in UP by the Congress Government were stopped by the SVD Government when it was in power and if so, whether these facilities will be restored to them ?

SHRI MUTHYAL RAO : I require notice.

SHRIMATI SAVITRI SHYAM : May I know whether it is a fact that concessions which are granted to these students are not available to them till the end of the academic year, on account of which they suffer a great deal ?

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON) : There have been persistent complaints that there have been delays in disbursement of these amounts to students belonging to scheduled castes and scheduled tribes, from certain States. The distribution is made by the State Government. The Central Government provides the money. This point has been raised in the Consultative Committee also.

We are proposing to look into this matter and see how these delays could be avoided.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि वह शिकायतें आप के पास कब से लगातार आ रही हैं, कितने वर्षों से लगातार शिकायतें आ रही हैं ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या जानबूझ कर काफ़ी हरिजन बच्चों को जो उनको स्कालरशिप्स और जो सहायता उन्हें मिलनी चाहिए वह योजनाबद्ध नहीं दी जाती है और वह सारा का सारा पैसा उत्तरप्रदेश में ही नहीं बल्कि वह सारे प्रान्तों के अन्दर पड़ा रहता है और उस का उपयोग नहीं किया जाता है ?

SHRI GOVINDA MENON : I was speaking of the complaints which were made by my colleagues in Parliament the other day in the Consultative Committee. As I submitted, the disbursement is made by the State Governments. It has to be looked into why, if at all, there are delays in the matter of disbursements. It is the earnest desire of the Department of Social Welfare to see that whatever is made available to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are disbursed to them in due time.

SHRI D. BASUMATARI : In view of the fact that no community has been declared as Scheduled Tribe in Uttar Pradesh may I know what steps they have taken to give scholarships to students belonging to those people who are not declared as tribes in the States and what is the number of people belonging to these classes and nomadic tribes who are not included in the Schedule ?

SHRI GOVINDA MENON : We deal with people who have been included in the Schedule as Scheduled Caste or Scheduled Tribe. As the hon. House knows, there is a Bill pending before a Select Committee to revise the castes, communities etc., to be included in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If there are any Scheduled Castes or Tribes in Uttar Pradesh who have not been included in the Schedule, I would request him to try to persuade the Select Committee to include their names.

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है तो उस के लिए क्या कोई कमेटी बनाई गई है, यदि हां, तो उस कमेटी में किन किन लोगों को रखा गया है ?

बिहार में भी इस तरह की कमेटीज के द्वारा बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और इसके लिए वहां एक हिन्दू पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति समिति बनी हुई है । और दूसरी मुस्लिम पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति समिति बनी हुई है, इस सैकुलर डेमोक्रेसी में भी वहां ऐसा चलता है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के नाम छात्रवृत्ति समितियों को दिये गये हैं ?

SHRI GOVINDA MENON : The question of determining the persons belonging to the backward communities is left to the State Government under the Constitution. If the question is whether in Uttar Pradesh and Bihar committees have been appointed in this respect, I would like to have notice. I have no information.

दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई योजनाएं

\+

*692. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई वे कौन-कौन सी योजनायें हैं जो इस समय उन के मन्त्रालय में विचाराधीन हैं;

(ख) ये योजनाएं किन-किन तारीखों को भेजी गई थीं और वे इस समय किस अवस्था में हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन योजनाओं के निपटारे में काफी समय लग रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इनके बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (DR. SHRIMATI PHULRENU GUHA): (a) Only one scheme *viz.* Establishment of a Government School for the Blind Children is under consideration.

(b) The scheme was received in the Department in October, 1968, and is being examined.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise. The final decision is, however, likely to be communicated to the Delhi Administration shortly.

श्री भारत सिंह चौहान : दिल्ली प्रशासन ने जो योजना भेजी है उसमें और केन्द्र की योजना में क्या कुछ अन्तर है और क्या यह कारण है कि उस में विलम्ब हो रहा है ?

DR. SHRIMATI PHULRENU GUHA : When a scheme is forwarded by any organisation or State, it has to be looked into from all sides; so, naturally, it takes a little time. We have received it only in October.

श्री हुकम चन्द कछवाय : सवाल यह था कि क्या कुछ अन्तर है ?

श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : हैरानी की बात है कि मन्त्री महोदया ने जो उत्तर दिया है वह तथ्यों के विपरीत है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की योजनायें आपके मन्त्रालय में आती हैं या होम मिनिस्ट्री में आती हैं ? क्या यह सत्य नहीं है कि दिल्ली प्रशासन की ओर से हरिजनों के लिए प्री-कम्पीटीशन ट्रेनिंग की एक योजना भेजी गई है, क्या यह भी तथ्य नहीं कि उनको दस्तकारी के काम में प्रोत्साहन देने के लिए एक केन्द्र खोलने की योजना भी उन्होंने भेजी है, क्या एक योजना हरिजनों के लिए मकान बनाने की भी आपके पास नहीं आई है ? क्या आपने इसके बारे में होम मिनिस्ट्री से पूछा है ?

DR. SHRIMATI PHULRENU GUHA : I need notice. The schemes that they mentioned referred only to our Department; so, naturally, we looked into them only.

श्री हुकम चन्द कछवाय : बीस दिन पहले यह प्रश्न दिया गया था । इसके बारे में पहले से मन्त्री महोदय होम मिनिस्ट्री से पूछ सकते थे ।

श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मैंने सवाल पूछा है कि कोई योजना आई है, इन्होंने कहा है कि नहीं आई है ।

I have definite information that these schemes were submitted to the Home Ministry.